Reservation facility for onward and return journeys in N.E.

2289. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how far the facility of reservation system can be extended by the Computer Reservation counter opened at the State capitals of the North-Eastern Region; and

(b) when the facility of onward and return journeys for all Rail lines be received from the centres in this region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) All the non-rail head State Capitals of Shillong, Imphal, Agartala, Gangtok, Itanagar, Kohima and Aizawl have been provided computerised passenger reservation facilities and as far as facility of return and onward journey reservation facilities from and to these places is concerned a project has been undertaken for networking of the five systems of Calcutta, Mumbai, Chennai, Delhi and Secunderabad. The software for networking has already been developed. The first phase of project has been successfully completed by linking Delhi, Secunderabad and Calcutta systems. With this, passengers at the State Capitals of North Eastern Region will also be able to get onward and return journey reservation across all the computerised terminals by all trains originating on Northern, North Eastern, Eastern, South Eastern, Northeast Frontier and South Central Railways. It is expected that the whole networking project would be completed by March, 1999 by linking Mumbai and Chennai also. This will bring all Passenger Reservation System (PRS) locations under the network enabling Passengers all over the country to get onward and return journey reservation facilities at all computerised passenger reservation centres of Indian Railways.

रेलवे में बुक किए गए माल के गंतव्य स्थल तक न पहुंचने पर दावा करना

2290. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल मार्ग द्वारा माल भेजने के लिए बुक किए गए ऐसे माल गंतव्य स्थल तक न पहुंचने पर उक्त माल के मालिक को इस संबंध में दावा करने का हक प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक कितनी-कितनी राशि के कितने दावे प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या इन दावों का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर से अंत तक कितने दावों का और कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया और क्या सरकार द्वारा इन दावों के भुगतान के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 246.88 करोड़ रु० की राशि वाले कुल 46152 दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) जी हां, दावों के सभी मान्य मामले मैरिट के आधार पर निपटा दिए जाते हैं केवल उन मामलों को छोड़कर जहां परेषणों का पता लगा लिया गया है तथा दावाकर्त्ताओं को सुपुर्दगी की गयी है।

(घ) और (ङ) दावे के 19959 मामलों में 575.33 लाख रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रेलवे दावों के निपटान के लिए निम्नलिखित लक्ष्य अवधियां निर्धारित की गई हैं:—

(i) मालडिब्बों/पूरे परेषणों की गैर-सुपुर्दगी के दावे	6 महीने